भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1224
उत्तर देने की तारीख-11/12/2023

केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा संचालित सरकारी

1224. श्री संजय जाधव:
श्री ओम पवन राजेनिंबालकर:

क्या **शिक्षा**

(क) क्या केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा संचालित देश के सभी सरकारी विद्यालयों में अपेक्षित संख्या में शिक्षक उपलब्ध हैं;
(ख) क्या सरकार को सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी की जानकारी है;
(ग) यदि हां, तो महाराष्ट्र के विद्यालयों में शिक्षकों की क्या स्थिति है;
(घ) क्या सरकार द्वारा ऐसे विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए पर्याप्त शिक्षक-छात्र अनुपात सुनिश्चित करने के लिए कोई विशिष्ट योजना कार्यान्वित की जा रही है/कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) और (ख): स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि सेवानिवृत्ति, इस्तीफे और छात्रों की संख्या में वृद्धि/नए स्कूलों के कारण अतिरिक्त आवश्यकताओं जैसे कारकों की वजह से रिक्तियां उत्पन्न होती रहती हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग समय-समय पर समीक्षा बैठकों और सलाह के माध्यम से राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने और उनकी तर्कसंगत तैनाती के लिए अनुरोध करता है। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के दौरान सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की संख्या इस प्रकार है:-

	सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या										
	कुल	प्राथमिक	उच्चतर प्राथमिक		माध्यमिक			उच्चतर माध्यमिक			
		(1-5)	(1-8)	(6-8)	(1-10)	(6-10)	(9-	(1-	(6-	(9-	(11-
भारत	4882446	1769688	1280573	227723	225132	283946	71495	353471	509522	129711	31185

स्रोत: यूडाइस+

(ग): शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए महाराष्ट्र के स्कूलों में शिक्षकों की स्थिति इस प्रकार है:

	शिक्षकों की संख्या - सभी प्रकार के प्रबंधन

	कुल	प्राथमिक	उच्चतर प्राथमिक		माध्यमिक			उच्चतर माध्यमिक			
		(1-5)	(1-8)	(6-8)	(1-10)	(6-10)	(9-10)	(1-12)	(6-12)	(9-12)	(11-12)
	74858	14931	21206	383	1454	31864	4731	1609	1447	1499	2788

स्रोत: यूडाइस+

(घ) और (ड.): केंद्र सरकार, समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से समय-समय पर संशोधित निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 , स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए उचित छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का एक विषय है, अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। इन स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हो और समयबद्ध तरीके से पूरी हो।

*****